शुगर प्रॉडक्शन की राह में सब्सिडी का रोड़ा

रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी की मांग को लेकर अड़ीं महाराष्ट्र की मिलें

"पिछले साल हमें रॉ शुगर के लिए प्रति किलो 25.50 रुपये की कीमत मिली थी जबकि इस साल प्राइस 22 रुपये किलो है। पिछले साल हमने सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट सब्सिडी की घोषणा से पहले ही अधिकांश रॉ शुगर एक्सपोर्ट कर दी थी

बी बी थंबोर

सेक्रेटरी, वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन

[जयश्री भोंसले | पुणे]

महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने अभी तक रॉ शुगर का उत्पादन शुरू नहीं किया है। इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट्स पर सब्सिडी दिए जाने की घोषणा के बाद ही प्रॉडक्शन शुरू होने की संभावना है।

पिछले साल राज्य में शुगर मिल्स ने नवंबर की शुरुआत में ही रॉ शुगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जबकि सरकार ने इसके बहुत समय बाद सब्सिडी की घोषणा की थी। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। पिछले साल के मुकाबले इस बार इंटरनेशनल लेवल पर रॉ शुगर की कीमतों में गिरावट आई है और इस वजह से शुगर मिल्स इस बार एहतियात बरत रही हैं।

नेचुरल शुगर एंड एलायड इंडस्ट्रीज (एनएसएआई) के चेयरमैन और एमडी और वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन (डब्लूआईएसएमए) के सेक्रेटरी बी बी थंबोर ने बताया कि अभी तक रॉ और रिफाइंड शुगर का प्रॉडक्शन शुरू नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा, 'पिछले साल हमें रॉ शुगर के लिए प्रति किलो 25.50 रुपये की कीमत मिली थी जबकि इस साल प्राइस 22 रुपये प्रति किलो है। पिछले साल हमने सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट सब्सिडी की घोषणा से पहले ही अधिकांश रॉ शुगर एक्सपोर्ट कर दी थी।' उन्होंने कहा, 'उस समय यह हमारे लिए अफोर्डेबल था क्योंकि रॉ शुगर का प्रॉडक्शन कॉस्ट व्हाइट शुगर के मुकाबले 2 रुपये प्रति किलोग्राम कम था।' पिछले साल एनएसएआई ने 10,000 टन रॉ शुगर एक्सपोर्ट किया था।

कोल्हापुर के वरना को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरी के एमडी वी एस चव्हाण ने कहा, 'सब्सिडी मिलने के बाद हम रॉ शुगर का प्रॉडक्शन करने की हालत में होंगे।'

शुगर मिल्स के मुताबिक, अभी तक एक्सपोर्टर्स ने रॉ शुगर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। गन्ने की कीमतों को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के बावजूद करीब 23 मिलों ने पेराई का काम शुरू कर दिया है। इनमें से अधिकतर मिलें राज्य के बड़े नेताओं की हैं। पेराई सीजन की शुरुआत अक्टूबर से होती है।

एक चीनी मिल मालिक ने अपना नाम नहीं छापे जाने की शर्त पर बताया, 'हम पिछले साल इंटरेस्ट फ्री लोन की वजह से किसानों को गन्ने की कीमत का भुगतान कर सके। इस साल हमें किसानों को पेमेंट करने में परेशानी हो रही है।' महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बाबर ने कहा, 'शुगर प्राइस में गिरावट और गन्ने के एफआरपी में बढ़ोतरी के अलावा रॉ शुगर के एक्सपोर्ट पर सब्सिडी नहीं दिए जाने की हालत को देखकर लगता है कि महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री वित्तीय संकट के जाल में फंस सकती है।'

महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार के बनने की बाद अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। इंडस्ट्री को राज्य की नई सरकार से राहत के उपायों की उम्मीद है।

घोषणाओं पर नजर

- **केंद्र सरकार** की तरफ से एक्सपोर्टर्स पर सब्सिडी दिए जाने की घोषणा के बाद ही शुगर मिलों की ओर से प्रॉडक्शन शुरू होने की संभावना है
- **पिछले साल** राज्य में शुगर मिल्स ने नवंबर की शुरुआत में ही रॉ शुगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जबकि सरकार ने इसके बहुत समय बाद सब्सिडी की घोषणा की थी
- **महाराष्ट्र देश** का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, इसलिए यहां की इंडस्ट्री की सेक्टर में ज्यादा दखल रहती है

इकनॉमिक टाइम्स
6/11/14